एक कठिन घटक है।

प्रारूप नीति में विकसित भूमि, अर्द्ध संरचना, वित्त, नवीन प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी भवन निर्माण सामग्रियों की व्यवस्था तथा कानूनी बाधाओं को समाप्त करने आदि जैसे कई उपायों के माध्यम से बढ़ते हुए शहरीकरण द्वारा उत्पन्न आवास समस्याओं पर काबू पाने के लिये विभिन्न नीतियों की रूप-रेखा भी प्रस्तुत की गयी है।

विदिशा रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल का निर्माण

1752. श्री राघवजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के विदिशा रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल निर्माण से संबंधित कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) ठेकेदार को इस कार्य के लिये कितनी राशि का भुगतान किया गया था तथा यह भुगतान कब किया गया था, यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक इस्पाती ढांचे का निर्माण हो गया है। कुल मिलाकर 30% प्रगति हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ठेकेदार ने अगस्त, 1990 में काम छोड़ दिया था। उससे पहले लगभग 6.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया था। ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गयी है तथा ठेके की शर्तों के तहत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। काम को विभागीय आधार पर शुरू करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

Bansagar Agreement, 1973 on Sone River

1753. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement known as Bansagar Agreement was signed in 1973 between Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh for equitable sharing of water from the Sone river system;

(b) whether it is also a fact that the terms of this agreement are being violated by Uttar Pradesh and Madhya Pradesh by the diversion of Sone river water to hydel projects; and

(c) if so, what steps Government would take to ensure an equitable water supply to Bihar?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) to (c) Yes, Sir. The Clause 9 of Banasgar Agreement states that as the hydrology of river Sone and its trimutaries is not well established and as Ganga Waters are abundantly available for utilisation by by lift, a special River Commission may be set up for a study of Sone river and drawing up a comprehensive plan for the region taking into account any re-adjustment in he use of water considered necessary by the States. Accordingly, Sone River Commission was set up. It submitted the revised assessment of available waters. During inte-vening period, different uses have emerged, which were not considered earlier. Keeping this in view, a meeting of Chief Minister of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh was marginal re-adjustment of water uses,

integrated operation of reservoirs and establishment of Sone River Authority. After discussion, it was decided to meet again to take a final view. Further meeting has not taken place.

Illegal Pepsi Depot in Delhi

1754. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Government concern at illegal pepsi depot" which appeared in the Indian Express dated 18th August, 1991;

(b) if so, whether Government have asked DDA to explain how this illegal construction which has effectively blocked the DDA's developmental plan for the area has been allowed, if so, the reasons therefor and the details thereof; and

(c) whether Government propose to get the land vacated from pepsi; if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Action under Section 30 (1) of Delhi Development Act, 1957 was initiated by DDA against the unauthorised builders.

(c) Demolition orders under Delhi Development Act were passed against the unauthorised builders (Pepsi Cola) but they obtained stay orders from the Court. In compliance with the directive from the Court, fresh opportunities were given to the unauthorised builders and again demolition orders have been passed. The case about acquisition of land is also being contested.

News item under caption 'Clugging its way into losses, train to Gandhinagar finds few takers

1755. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the 'Economic Times' dated the 18th August, 1991 under the caption 'Clugging its way into losses, train to Gandhinagar finds few takers' regardin cancellation of 119/120 mixed train running between Ahmedabad and Gandhinagar; and

(b) if so, what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) Load of 119/120 Ahmedabad Gandhinagar Mixed has been reduced from 12 to 3 coaches to save expenditure

मध्य प्रदेश में चूना पत्थर क्षेत्रों को आरक्षण से मुक्त किया जाना

1756. **श्रीमती रहत कुमारी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में सीमेन्ट उद्योगों को स्थापना के लिये सतना जिले के चूना पत्थर वाले कुछ क्षेत्रों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, के नियंत्रण से मुक्त किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्व तं प्रभार) (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ खनिजधारी क्षेत्रों को आरक्षण मुक्त करने संबंधी मध्य प्रदेश शासन के प्रस्ताव में सतना जिले के 238 गांवों के चूना पत्थरधारी क्षेत्रों को आरक्षण-मुक्त करने की बात भी शामिल है, सरकारी सैक्टर में यह विदोहन के लिये आरक्षित है । राज्य